

प्रेस विज्ञप्ति

"तन्त्रिक पारिस्थितिक तंत्र हेतु – वानिकी अनुसंधान की भूमिका" पर राष्ट्रीय सम्मेलन

8 और 9 मई 2018, व.आ.वृ.प्र.सं, कोयम्बतूर

वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर "तन्त्रिक पारिस्थितिक तंत्र हेतु – वानिकी अनुसंधान की भूमिका" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह सम्मेलन 8 मई 2018 को श्री.सिद्धान्ता दास, भा.व.से, वन महानिदेशक और विशेष सचिव,पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,भारत सरकार के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस सत्र का शुभारंभ डॉ.मोहित गेरा, भा.व.से., निदेशक, वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान के द्वारा सभी का स्वागत करते हुये हुआ। उसके बाद निदेशक जी ने सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने भारत के वनों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

डॉ.एस.डी.शर्मा, उप महानिदेशक(अनुसंधान) ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि पिछले वर्ष से भा.वा.अ.शि.प द्वारा शुरू की गई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला में "तन्त्रिक पारिस्थितिक तंत्र हेतु – वानिकी अनुसंधान की भूमिका" पर राष्ट्रीय सम्मेलन ही पहला सम्मेलन है। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पहले सभी के द्वारा भामक कॉल के रूप में दिखाया गया था लेकिन आजकल सभी विश्वास करने लगे हैं। पेड़ों में फूलों का बदलता रूप, पेड़ों का उच्च दृष्टिकोण, बढ़ता तापमान, अनियत हिमपात और वर्षा में बदलाव और इसी तरह के कई अध्ययन से यह साबित हुआ है कि वास्तव में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के सभी प्रमुख वन तटीय क्षेत्रों से अल्पाइन वनों और रेगिस्तानी क्षेत्रों तक के विशिष्ट प्रजातियाँ अनुमानित जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है।

डॉ.एस.सी.गैरोला, भा.व.से., महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून ने अपने वचन में बताया कि वन, पेड़ों के विकास और मिट्टी के कार्बन में वृद्धि के माध्यम से एकत्रित वैश्विक कार्बन स्टॉक पेश करते हैं और विश्वभर में कार्बन के 250 गिगा टन स्टोर करते हैं। वनों का पुनर्वास और धारणीय प्रबंधन वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि कर सकते हैं जबकि वनों की कटाई और गिरावट के परिणाम स्वरूप कार्बन स्टॉक में कमी आती है। यह अनुमान

लगाया गया था कि विश्व स्तर पर वनों की कमी का कारण वर्ष में 0.22 गीगा टान घट रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और यह कृषि, स्वास्थ्य, जल और वानिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वन पारिस्थितिक तंत्र CO₂ के लिये सिंक के रूप में कार्य कर रहे हैं जो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है। गैर वानिकी प्रयोजनों के लिये वन भूमि का विखंडन और परिवर्तन CO₂ उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है जबकि वानिकी क्षेत्र CO₂ उत्सर्जन को कम करने और वनस्पति एवं मिट्टी में अनुक्रमण द्वारा वायुमंडल से संचित CO₂ को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान में प्रबंधन दृष्टिकोण से यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि जटिल वनों को संरचनात्मक रूप में बनाये रखकर वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को कम करने का इरादा रखते हैं। जलवायु परिवर्तन की कमजोरी को कम करने के लिये शमन कार्यक्रमों एवं अनुकूली प्रथाओं को वन अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भा.वा.अ.शि.प ने राष्ट्रीय REDD plus रणनीति तैयार की है और उसे सरकार को सौंप दिया है ताकि देशों के वनों में REDD plus फ्रेमवर्क का लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य वन संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और कार्बन में वृद्धि के लिये वन समुदायों को पुरस्कृत करना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वनों के लिये राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर "जलवायु परिवर्तन प्रभाव और भेदना मूल्यांकन" पर अनुकूलित रणनीतियों को विकसित करना आवश्यक है।

श्री.सिद्धांता दास, भा.व.से., वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल पर 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक सतह का तापमान 1.5 सए 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इससे उम्मीद है कि इस शताब्दी के दौरान वैश्विक जलवायु सिस्टम में और भी गर्माहट एवं कई बदलाव आयेंगे और पिछली शताब्दी के मुकाबले अधिक गंभीर होने की संभावना है।

उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक विचार-विमर्शों ने सन 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की। उन्होंने 2015 में पेरिस के साथ किये गये करार के बारे में भी उल्लेख किया जिसमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों का आग्रह करते हुये कम सए कम 2 डिग्री सएल्सियस सए नीचे वैश्विक तापमान

में वृद्धि को सीमित करने लक्ष्य की पुष्टि की। इस पेरिस करार के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को अनुकूलित करने की क्षमता को बढ़ाने एवं अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने की क्षमता को बढ़ाने की दीर्घकालीन लक्ष्य पर भी सहमत हुए। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्या को देखकर भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने का सवैच्छिक लक्ष्य घोषित किया।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य देश के वनों और पेड़ के कवर को 5मी तक बढ़ाने एवं आजीविका समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ वन भूमि के 5मी पर वन एवं पेड़ के कवर की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस वर्ष लगभग 100 मिलियन टन CO2 समकक्ष कार्बन अनुक्रमण को बढ़ाने की उम्मीद है। उन्होंने देश के हरित कवर को बढ़ाने और ग्रामीण समुदाय के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सडकों पर बागानों की स्थापना की संभावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा नदी के लिये वानिकी हस्तक्षेप के सआथ नदियों के कायाकल्प के लिये एक नया समग्र दृष्टिकोण भी शुरू किया गया है जिससे नदियों के प्रदूषित हिस्सों की खोई हुई पारिस्थितिक को पुनर्स्थापित करने के लिये जल और पर्यावरण प्रबंधन को एक साथ लिया गया है।

उन्होंने भारत के वनों पर संभावित जलवायु परिवर्तन प्रभावों के कुछ उदाहरण भी दिये जिसमें सिक्किम में कई पक्षी प्रजातियों ने ऊँचाई सीमा को 700 मीटर ऊपर की सईभा तक स्थानांतरित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पुष्प प्रजातियों जैसे Rhododendron में ध्वन्यात्मक परिवर्तन की सूचना दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से चम्बा, कुल्लु, शिमला, कंगडा और मंडी के जिलों में 2030 तक बदलते माहौल सबसे कमजोर होंगे।

सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अंत में डॉ.एस.मुरुगेसन, समूह समन्वयक (अनुसंधान) एवं संयोजक ने धन्यवाद प्रस्ताव किया।